विषय सूची

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	**मांग संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग**	
(i)	आईआईपीडीएफ स्कीम (सीएस)	1
2.	**मांग संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग**	
(i)	कोबिड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)	2
(ii)	सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	2
(iii)	प्रघानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रघानमंत्री सूरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	2
(iv)	प्रघानमंत्री वय वदंना योजना (पीएमवीवीवाई) (सीएस)	3
(v)	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) : वरिष्ठ नागरिकों (सीएस) के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सहायता	3
(vi)	भारत- स्विक सहयोग - 6 के तहत दावों के लिपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	3
(vii)	अटल पेंशन योजना (सीएस)	3-4
3.	**मांग संख्या 33 - लोक उद्यम विभाग**	
(i)	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना	5
(ii)	सीपीएसईज और एसएलपीईज से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान विकास और परामर्श	5

आर्थिक कार्य विभाग

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2023-24	प्रतिफल 2023-24*			परिणाम 2023-24*		
	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
(i) आईआईपीडीएफ स्कीम (सीएस)						
25	पीपीपी मोड पर शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तीय/वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार	अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के प्रस्तावों की कुल संख्या	लक्ष्य प्रतिसंवेदी (एमिनेबल) नहीं है	अवसंरचना में उन्नत निजी क्षेत्र भागीदारी	सहयोग प्राप्त परियोजनाओं (करोड़ रुपये में) में कुल निवल निजी निवेश	लक्ष्य प्रतिसंवेदी (एमिनेबल) नहीं है
		परियोजनाओं की टीपीसी को अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया (करोड़ रुपये में)	लक्ष्य प्रतिसंवेदी (एमिनेबल) नहीं है			
		कुल संवितरित निधि (करोड़ रुपये में)	लक्ष्य प्रतिसंवेदी (एमिनेबल) नहीं है			
		परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए निधि संवितरित की गई	लक्ष्य प्रतिसंवेदी (एमिनेबल) नहीं है			

* मांग आधारित योजना होने के नाते, अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित और विचारार्थ प्रस्तुत परियोजनाओं के वार्षिक लक्ष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2023-24	प्रतिफल 2022-23			परिणाम 2023-24		
	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
(i) कोबिड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)						
100 (प्रस्तावित)	ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करके संपार्श्विक मुक्त ऋण को बढ़ावा देना जिससे सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के ऋण जोखिम को कम किया जा सके	योजना के तहत गारंटीकृत ऋण खातों की संचयी संख्या	2300 1918 (दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार)	पात्र स्वास्थ्य परियोजनाओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई निधियों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि	लागू नहीं
(ii) सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)						
100 (प्रस्तावित)	ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करके संपार्श्विक मुक्त ऋण को बढ़ावा देना जिससे सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के ऋण जोखिम को कम किया जा सके	योजना के तहत गारंटीकृत ऋण खातों की संचयी संख्या	योजना मार्च, 2022 तक चालू थी।	पात्र स्वास्थ्य परियोजनाओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई निधियों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली ऋण की राशि	लागू नहीं
(iii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीना योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)						
1.50 (प्रस्तावित)	पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन अभियान	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या	i. माह में दो बार प्रमुख अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय समाचार-पत्र में प्रिंट विज्ञापन ii. विभिन्न टीवी चैनलों पर दैनिक आधार पर टीवीसी iii. विभिन्न रेडियो चैनलों पर दैनिक आधार पर रेडियो जिंगल iv. पूरे वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों पर चित्रकारी	पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन को बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाना	मई 2023 में पॉलिसी वर्ष के समाप्त होने से लेकर दोनों योजनाओं के अन्तर्गत नामांकन में प्रतिशत वृद्धि	मई 2023 में पॉलिसी वर्ष की समाप्ति के बाद से दोनों योजनाओं के तहत नामांकन में प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है: पीएमजेजेबीवाई-15% पीएमएसबीवाई-10%

(iv) प्रधानमंत्री वय वंदा योजना (पीएमवीवीवाई) (सीएस)						
189.70 (प्रस्तावित)	प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना ।	वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन योजना का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या ।	योजना 31 मार्च 2023 तक अभिदान के लिए खुली है; इसके बाद किसी को नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।	प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की कवरेज में वृद्धि और सुनिश्चित प्रतिफल में कमी का वहन सरकार द्वारा किया जाता है।	प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों में प्रतिशत वृद्धि	योजना 31 मार्च 2023 तक अभिदान के लिए खुली है; इसके बाद किसी को नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(v) **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) : वरिष्ठ नागरिकों (सीएस) के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सहायता**						
111.47 (प्रस्तावित)	नये व्यवसायों के लिए यह योजना बंद हो चुकी है। केवल मौजूदा अभिदाताओं को सरकार की सहायता से गारंटीकृत प्रतिलाभ का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार, कोई नया प्रतिफल या परिणाम नहीं है।					
(vi) **भारत-स्विस सहयोग - VI के तहत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान**						
0.83 (प्रस्तावित)	गैर कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा ऋण के प्रवाह में वृद्धि की जा सके ।	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड को दावों के रूप में जारी राशि का प्रतिशत	100%	आस्ति सृजन और पूंजी निर्माण के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र संबर्धन	इस परियोजना के तहत ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र ऋण के प्रति भारत सरकार का विदेशी प्रशासन को देय भुगतान / प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष निधि से नाबार्ड को पुनर्वित्त राशि जारी करना (करोड़ रुपये में)	0.83
(vii) **अटल पेंशन**	**योजना (सीएस)**					
वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2023-24*	**आउटपुट 2022-23**		**परिणाम 2023-24**			
	प्रतिफल	**संकेतक**	**लक्ष्य 2023-24****	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2023-24^**
245 (प्रस्तावित)	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन	एपीवाई सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	245	बेहतर जागरूकता के कारण अभिताओं को अधिक कवरेज, अटलता का स्तर और वृद्धावस्था सुरक्षा	नामांकित अभिदाताओं की संख्या	बैंकों और डाक विभाग को दिए गए नामांकन लक्ष्य
5 (प्रस्तावित)	अटल पेंशन योजना (एपीवाई के तहत प्रचार अभियान	प्रचार अभियानों के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	5	बेहतर जागरूकता के कारण अभिताओं को अधिक कवरेज, निरंतरता का स्तर और वृद्धावस्था सुरक्षा	नामांकित अभिदाताओं की संख्या	लक्ष्य उत्तरदायी नहीं है क्योंकि मीडिया अभियान के कारण एपीवाई के तहत होने वाले नामांकन की गणना करना संभव नहीं है

271 (प्रस्तावित)	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत भिन्नता निधि	भिन्नता निधियन के लिए स्वीकृत राशि	यह सुनिश्चित करने के लिए कि एपीवाई के प्रत्येक ग्राहक को 2035 से न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।	पेंशनभोगी समाज बनाने के उद्देश्य से, एपीवाई पेंशनभोगियों के बीच विश्वास लाएगा और पेंशन आधार का विस्तार करेगा।	2035 के बाद लाभान्वित होने वाले सदस्यों की संख्या।	लक्ष्य संशोधन योग्य नहीं है क्योंकि पेंशन वितरण 2035 से पहले शुरू नहीं होगा।

* *प्रस्तावित ब.अ. 2023-24*

** *वर्ष 2023-24 के बजटीय अनुमानों के आवंटन के आधार पर डीईए द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के प्रत्येक प्रतिफल संकेतक के बदले लक्ष्य निर्धारित किया जाए क्योंकि ये वित्त वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली राशि से संबंधित हैं*

^ *वित्त वर्ष 2023-24 के परिणाम संकेतकों के लिए नामांकित अभिदाताओं की संख्या के संबंध में लक्ष्यों को वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही तक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा।*

लोक उद्यम विभाग

विभाग की सीएस/सीएसएस योजनाओं के साथ 500 करोड़ रुपए से कम के परिव्यय के लिए आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) 2023-24

(i) परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना

वित्तीय परिव्यय (रुपए करोड़ में) 2023-24	आउटपुट 2023-24			आउटकम 2023-24		
	आउटपुट	सूचक	लक्ष्य 2023-24	आउटकम	सूचक	लक्ष्य 2023-24
3.40	1. परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक्कृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन ।	1.1 प्रशिक्षित वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों/उनके आश्रितों की संख्या	1500	1. परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक्कृत कर्मचारियों के वीआरएस/ वीएसएस पुनर्नियोजन दायरे में वृद्धि	1.1 पुनर्नियोजित वीआरएस/ वीएसएस विकल्पधारियों/ आश्रितों का %	65%
(ii) सीपीएसईज और एसएलपीईज़ से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और परामर्श						
6.51	1. सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करना।	1.1सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	25	1. सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का कवरेज	1.1 पूर्व वर्ष की तुलना में प्रशिक्षित कार्यपालकों की संख्या में % वृद्धि/कमी	10%
		1.2.सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के लिए आयोजित की गई कार्यशालाओं की संख्या	15		1.2. पूर्व वर्ष की तुलना में आयोजित कार्यशालाओं की संख्या में % वृद्धि/कमी	10%
		1.3.सीपीएसईज़ के निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए संचालित ओरिएंटेशन कार्यक्रमों की संख्या	6		1.3. पूर्व वर्ष की तुलना में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या में % वृद्धि/कमी	10%

INDEX

Sl. No.	Departments	Page No.
1.	**Demand No.30- Department of Economic Affairs**	
(i)	IIPDF Scheme (CS)	9
2.	**Demand No.32- Department of Financial Services**	
(i)	Loan Guarantee Scheme for COVID Affected Sectors (LGSCAS)	10
(ii)	Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (CGSMFI)	10
(iii)	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) (Publicity and Awareness)	10
(iv)	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) (CS) :	11
(v)	Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) : Interest subsidy to LIC for Pension Plan for Senior Citizens (CS)	11
(vi)	Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation –VI	11
(vii)	Atal Pension Yojana (CS)	11-12
3.	**Demand No.33- Department of Public Enterprises**	
(i)	Counselling, Retraining and Redeployment (CRR) scheme	13
(ii)	Research, Development and Consultancy on generic issues related to CPSEs and SLPEs	13

Financial Outlay (Rs. in Cr.) 2023-24	OUTPUTS 2023-24*			OUTCOME 2023-24*		
	Output	**Indicators**	**Target 2023-24**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2023-24**
(i) IIPDF Scheme (CS)						
25	Improve financial / commercial viability of infrastructure projects undertaken on PPP mode	Total number of Projects proposals approved by Approval Committee	Target not amenable	Improved Private Sector participation in infrastructure	Total Net Private investment in supported projects (in Rs. Crores)	Target not amenable
		TPC of Projects accorded Final approval (Rs. in Crores)	Target not amenable			
		Total funding disbursed (Rs. in Crores)	Target not amenable			
		Number of projects for which funding disbursed	Target not amenable			

* *Being a demand-driven scheme, annual target of projects submitted for consideration and approved by Approval Committee, cannot be predicted accurately.*

Financial Outlay (Rs. In Cr.) 2023-24	OUTPUTS 2022-23			OUTCOME 2023-24		
	Output	**Indicators**	**Target 2023-24**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2023-24**
(i) Loan Guarantee Scheme for COVID Affected Sectors (LGSCAS)						
100 (proposed)	Encouraging collateral free lending by way of providing guarantee cover to loans thereby reducing the Credit Risk of the Member Lending Institutions	Cumulative number of loan accounts guaranteed under the scheme	2300 1918 (as on 31.10.2022)	Providing guarantee coverage for the funding provided by Scheduled Commercial Banks to eligible health care projects	Amount of loan to be sanctioned under the scheme by Member Lending Institutions	NA
(ii) Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (CGSMFI)						
100 (proposed)	Encouraging collateral free lending by way of providing guarantee cover to loans thereby reducing the Credit Risk of the Member Lending Institutions	Cumulative number of loan accounts guaranteed under the scheme	Scheme was operational till March, 2022	Providing guarantee to lending institution for funding provided by them to NBFC-MFIs or MFIs	Amount of loan to be sanctioned under the scheme by Member Lending Institutions	NA
(iii) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) (Publicity and Awareness)						
1.50(proposed)	Advertisement campaigns to drive awareness for PMJJBY and PMSBY	Number of advertisements issued during the financial year	i. Print advertisements in leading English, Hindi & regional newspapers twice a month ii. TVCs on different TV channels on daily basis iii. Radio jingles on different radio channels on daily basis iv. Wall paintings in rural areas throughout the year	Enhanced awareness to increase encrolments under PMJJBY and PMSBY	Percentage increase in the enrolment under both the schemes since the end of the policy year in May 2023	Percentage increase in the enrolment under both the schemes since the end of the policy year in May 2023 are as imder : PMJJBY -15% PMSBY-10%

(iv) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) (CS) :						
189.70 (proposed)	Coverage of senior citizens under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana	Number of senior citizens opting for the pension plan during the financial year	Scheme is open for subscription up to 31st March, 2023; No further enrolment will be allowed thereafter	Increased coverage of senior citizens and shortfall from the assured return borne by the Government under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana	Percentage increase in senior citizens under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana	Scheme is open for subscription up to 31st March, 2023; No further enrolment will be allowed thereafter
(v) Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY): Interest subsidy to LIC for Pension Plan for Senior Citizens (CS)						
111.47 (proposed)	Scheme is closed for new business. Only existing subscribers are being paid guaranteed return through support from the Government. As such, there are no new outputs or corresponding outcomes.					
(vi) Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation - VI						
0.83 (proposed)	Refinance by NABARD for non-farm sector to increase the flow of credit by banks for non-farm activities in rural areas	Percentage of amount released as claims to NABARD during FY 2023-24	100%	Promotion of non-farm sector, through asset creation and capital formation	Release of refinance amount to NABARD from a Special Fund to cover repayments/ commitments due from GoI to the foreign administration against the Rural Non-Farm Sector credit under the project (in Rs. cr.)	0.83

(vii) Atal Pension Yojana (CS)

Financial Outlay (Rs. In Cr.) 2023-24*	**OUTPUTS 2022-23**			**OUTCOME 2023-24**		
	Output	**Indicators**	**Target 2023-24****	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2023-24^**
245 (proposed)	Incentive to Atal Pension yojana (APY) Service providers (SPs)	Amount sanctioned for incentive to APY SPs (in Rs. Crore)	245	Better awareness leading to more coverage, persistency levels, and Old age security to the subscribers	Number of subscribers enrolled	Enrolment targets given to Banks and Department of Post
5 (proposed)	Promotional Campaign under Atal Pension Yojana (APY)	Amount sanctioned for Promotional campaigns (in Rs. Crore)	5	Better awareness leading to more coverage, persistency levels, and Old age security to the subscribers		Target not amenable as its not possible to calculate the enrolments that would happen under APY due to media campaign

271 (proposed)	Gap Fund under Atal Pension Yojana (APY)	Amount sanctioned for Gap funding	To ensure that every subscriber of APY will get minimum assured pension starting from 2035 onwards.	With the aim to create a pensioned society, APY will bring confidence amongst pensioners and enlarge the pension base.	Number of subscribes benefitted beyond 2035.	Target not amenable as pension disbursement will not start before 2035.

* *Proposed BE 2023-24.*

** *Targets against each of the output indicators for FY 2023-24 may be determined on allocation of Budgetary Estimates 2023-24 by DEA as these relate to amount to be sanctioned in FY 2023-24.*

^ *Targets for outcome indicators for FY 2023-24 in respect of number of subscribers enrolled would be finalised with the approval of Competent Authority by the 1st Quarter of FY 2023-24.*

Output-Outcome Monitoring Framework (OOMF) 2023-24 for CS/CSS Schemes of the Department with outlay of less than Rs. 500 crore

(i) Counseling, Retraining and Redeployment (CRR) scheme						
Financial Outlay (Rs. in Cr.) 2023-24	**OUTPUT 2023-24**			**OUTCOME 2023-24**		
	Output	**Indicators**	**Target 2023-24**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2023-24**
3.40	1. Redeployment of separated employees through counselling and training.	1.1. Number of VRS/VSS optees / their dependents trained.	1500	1. Increase the coverage of VRS/VSS redeployment of separated employees through counselling and training	1.1. % of VRS /VSS optees / dependents redeployed	65%
(ii) Research, Development and Consultancy on generic issues related to CPSEs and SLPEs						
6.51	1. To undertake research studies, trainings, seminars, workshops on generic issues related to CPSEs and SLPEs.	1.1. No of Training Programmes for executive of CPSEs and SLPEs conducted	25	1. Coverage of research studies, training and workshops on generic issues to CPSEs and SLPEs.	1.1. % increase/ decrease in no. of trained executives over previous year	10%
		1.2. No. of workshops for executives of CPSEs and SLPEs held	15		1.2. % of increase/ decrease in no. of workshops organized over previous year	10%
		1.3. No. of orientation programmes for capacity building of Directors of CPSEs conducted	6		1.3. % of increase/ decrease in number of participated directors over previous year	10%